भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3906

17 मार्च, 2020 को उत्तरार्थ

विषय : ग्रामीण कृषि बाजार

3906. श्री मितेष पटेल (बकाभाई) :

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 'ग्रामीण कृषि बाजारों' के अन्तर्गत कितनी 'मंडियां' स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त उद्देश्य के अनुसरण में राज्य-वार कितनी 'मंडियां' स्थापित की गई हैं;

(ग) उक्त 'मंडियों' में से कितनी मंडियों में साप्ताहिक मंडियां लगते हैं और कितनी 'मंडियां' प्रतिदिन लगती हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त 'मंडियों' में से कितनी 'मंडियों' में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं और कितनी मंडियों में उक्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) एवं (ख): राज्य कृषि विपणन विभागों/बोर्डों से प्राप्त सूचना के अनुसार देश में कुल 22941 ग्रामीण हाट हैं जिसमें से 11811 ग्रामीण हाट पंचायतों के नियंत्रण में हैं, 1274 ग्रामीण हाट कृषि उत्पाद हाट समितियों (एपीएमसी) के नियंत्रण में हैं।

सरकार ने 10,000 ग्रामीण कृषि मंडियों (ग्राम) में विपणन अवसंरचना के विकास के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सहायता का लाभ उठाने हेतु नाबार्ड के लिए कृषि मंडी अवसंरचना निधि (एएमआईएफ) के रूप में 2000 करोड़ रु. का पहले ही अनुमोदन किया है। सहायता प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एएमआईएफ के प्रचालनात्मक दिशा-निर्देश पहले ही जारी कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण कृषि मंडियों को संचालित करने एवं उनका प्रबंधन करने के लिए मॉडल दिशा-निर्देश भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मार्गदर्शन करने के लिए परिचालित किए गए हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), भारत सरकार, ग्रामीण कृषि मंडियों के विकास के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा) के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के द्वारा पंचायतों के नियंत्रण में आने वाली ग्रामीण हाट का विकास एवं भौतिक अवसंरचना का उन्नयन कर रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार मनरेगा के अंतर्गत भौतिक अवसंरचना/सुविधाओं का 476 ग्रामीण हाट में विकास किया गया है और 820 ग्रामीण मंडियों में इनका विकास किया जा रहा है। इसकी राज्यवार सूची **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ग) एवं (घ): कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग का संबद्ध कार्यालय - विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई), स्थान, आवधिक रूप से उसकी कार्य प्रणाली, विद्यमान अवसंरचना की स्थिति तथा सुविधाओं आदि का पता लगाने/मूल्यांकन करने के लिए विद्यमान ग्रामीण मंडियों का सर्वेक्षण कर रहा है। डीएमआई ने अभी तक 17285 ग्रामीण हाट का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है जिसमें से 73 प्रतिशत (12618) ग्रामीण हाट साप्ताहिक आधार पर संचालित हैं जबकि 11 प्रतिशत (1902) ग्रामीण हाट दैनिक आधार पर संचालित हैं।

उपरोक्त सर्वेक्षण के आधार पर ग्रामीण हाट में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का विवरण इस प्रकार है:-

मूलभूत सुविधाओं का नाम	**मूलभूत सुविधाओं वाली मंडियों (हाट) की सं. (%)**
चार दिवारी/फैंसिंग	1383 (8%)
शैड सहित/शैड के बगैर उठे हुए प्लेटफार्म	2593 (15%)
आंतरिक पक्की सड़क	2420 (14%)
शौचालय	691 (4%)
विद्युत	4148 (24%)

अनुबंध – I

लोसअताप्रसं. 3906

मनरेगा के तहत ग्रामीण हाट के विकास एवं उन्नयन की स्थिति

(09.03.2020 तक)

क्र.सं.	राज्य /संघ राज्य क्षेत्र	इसके प्रारंभ से चल रहा कार्य	प्रारंभ से पूरा हुआ कार्य
1.	आंध्र प्रदेश	111	14
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	3
3.	असम	9	1
4.	बिहार	29	5
5.	छत्तीसगढ़	85	29
6.	गुजरात	2	1
7.	हरियाणा	0	1
8.	हिमाचल प्रदेश	45	7
9.	जम्मू और कश्मीर	28	4
10.	झारखंड	1	0
11.	कर्नाटक	17	7
12.	केरल	16	4
13.	मध्य प्रदेश	55	69
14.	मणिपुर	2	23
15.	मेघालय	9	3
16.	मिजोरम	39	99
17.	नागालैंड	0	2
18.	ओडिशा	21	28
19.	पंजाब	7	2
20.	राजस्थान	42	35
21.	सिक्किम	0	3
22.	तमिलनाडु	48	19
23.	तेलंगाना	7	1
24.	त्रिपुरा	2	7
25.	उत्तर प्रदेश	63	62
26.	उत्तराखंड	29	11
27.	पश्चिम बंगाल	150	36
28.	पुडुचेरी	1	0
कुल		**820**	**476**

*****